भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2871

उत्तर देने की तारीख-07/08/2023

पीएम-उषा का कार्यान्वयन

†2871. **श्री चंद्र शेखर साहू:**

श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों, विशेषकर ओडिशा में जल्द ही प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पीएम-उषा के घटक कॉलेजों (प्रत्यायित और गैर-प्रत्यायित कॉलेजों) को सुदृढ़ करने के लिए संकाय पदों को नियमित रूप से भरने हेतु चयन संबंधी मानदंडों को संशोधित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विश्वविद्यालयों (प्रत्यायित और गैर-प्रत्यायित विश्वविद्यालय) के घटक को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख): सरकार ने 2023-24 से 2025-26 की अवधि हेतु 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना को मंजूरी दी है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश ओडिशा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। यह https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/pm-usha_guidelines.pdf पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): पीएम-उषा के तहत, 'कॉलेजों (प्रत्यायित और गैर-प्रत्यायित कॉलेजों)' को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान सहित सभी घटकों के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु विभिन्न मानदंड शामिल किए गए हैं। ये मानदंड संस्थान के प्रदर्शन की स्थिति के आधार पर अलग-अलग वेटेज देते हैं, जिसमें संस्थानों में नियमित मोड में भरे गए संकाय का प्रतिशत भी शामिल है।

(ङ) और (च): पीएम-उषा के घटकों में से एक घटक 'विश्वविद्यालयों (प्रत्यायित और गैर-प्रत्यायित विश्वविद्यालयों) को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान' है, जिसमें अनुमोदित विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

*****